भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1879

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानसून का प्रभाव

1879. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 के मानसून के दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक स्थान पर दर्ज क्षति का प्रकार और सीमा क्या है;

(ख) तत्काल बहाली, स्थायी सुधार कार्यों और दीर्घकालिक लचीलापन-वृद्धि उपायों के अंतर्गत वर्गीकृत प्रत्येक क्षतिग्रस्त राजमार्ग खंड की मरम्मत और पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या कमजोर चट्टान संरचनाओं, भारी वर्षा पैटर्न, प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा वाले बादल फटने और अपर्याप्त ढलान संरक्षण और जल निकासी प्रणालियों जैसी मानवजनित गतिविधियों के कारण ढलान की अस्थिरता ने इस तरह के नुकसान में भूमिका निभाई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) महत्वपूर्ण गलियारों पर यातायात आवागमन की बहाली की समय-सीमा क्या है;

(ङ) भू-सिंथेटिक सुदृढीकरण, ढलान स्थिरीकरण और भूस्खलन रोकथाम के लिए जालीदार अवरोधों की स्थापना और बादल फटने की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों सहित आपदा-रोधी अवसंरचना उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(च) क्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रिकवरी पुनर्निर्माण निधि के अंतर्गत धनराशि का उपयोग राजमार्ग की मरम्मत परियोजनाओं के लिए भी किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने के कारण 2025 मानसून के मौसम के दौरान क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विवरण, यातायात की बहाली की स्थिति, अस्थायी और स्थायी बहाली कार्यों की स्थिति, स्वीकृति की स्थिति और स्थायी बहाली के लिए समय-सीमा सहित संलग्न है।

ऐसे नुकसान के मुख्य कारणों में बारिश, बाढ़, कटाव, ड्रेनेज/संबंधित हाइड्रोलिक स्थितियों आदि के कारण तटबंधों का टूटना, भूस्खलन, फिसलन, सुरक्षा कार्यो, पुलिया आदि का नुकसान शामिल है।

सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ करने और अनुरक्षण की आवश्यकताओं को कम करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों या विधियों (वर्षा, भूभाग का प्रकार, मिट्टी की श्रेणी आदि जैसे कारकों के आधार पर) को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। इन तकनीकों या विधियों में उप-श्रेणी का स्थिरीकरण, उप-आधार/बेस में जियोसिंथेटिक प्रबलित परतें, कंक्रीट सड़कें/व्हाइट-टॉपिंग, स्थायी फुटपाथ, उच्च निष्पादन बिटुमिनस मिश्रण, संशोधित बिटुमेन/बिटुमिनस मिश्रण, फाइबर प्रबलित कंक्रीट, सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिश्रण आदि शामिल हैं। स्वचालित और कुशल मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण को अपनाया गया है जो क्लाउड-आधारित अनुरक्षण रिकॉर्ड और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करता है।

पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों सहित आपदा प्रतिरोधी राष्ट्रीय राजमार्गों के अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें ढलानों की खुदाई/कटाई/स्थिरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें शामिल हैं: -

i. उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए विशेष भूस्खलन प्रबंधन उपायों के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

ii. समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन प्रबंधन क्षेत्रों के लिए लागत प्रभावी दीर्घकालिक सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन हेतु नवंबर, 2024 में निर्णय लिया गया।

iii. अब से ढलान काटने और स्थिरीकरण कार्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के लिए सड़क निर्माण कार्य किए जाएँगे। सड़क निर्माण कार्य तभी प्रारंभ होंगे जब खंड-वार सुरक्षा उपाय पूरे हो जाएँगे।

iv. पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से संबंधित चिंताओं के समाधान हेतु अतिरिक्त संवर्धित और व्यवस्थित निदानात्मक उपायों हेतु नवंबर 2025 में एक व्यापक नीति परिपत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा।

v. राष्ट्रीय राजमार्गों पर भू-खतरे के शमन उपायों के तकनीकी सहयोग के लिए रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

vi. सुरंगों की भूवैज्ञानिक जाँच और भू-संकट संबंधी अध्ययन हेतु डेटा साझा करने पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

vii. राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय शैल यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम) के साथ सुरंग परियोजनाओं, सड़क परियोजनाओं, डीपीआर/निर्माण चरण के दौरान सुरंग के डिज़ाइन और रेखाचित्रों की समीक्षा/सबूत जाँच, उपकरणों और निगरानी उपकरणों की पर्याप्तता की जाँच, सुरंग सुरक्षा लेखा परीक्षा, कार्य पैकेज के लिए शैल यांत्रिकी और शैल इंजीनियरिंग पर आधारित वैज्ञानिक जाँच तैयार करने, अधिकारियों को प्रशिक्षण आदि के लिए व्यापक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

viii. शिलांग-सिलचर ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सहकर्मी समीक्षा हेतु एनआईआरएम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पहाड़ी ढलानों की अस्थिरता का आकलन करने के लिए यंत्रीकरण और वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग करते हुए दिशानिर्देशों के विकास हेतु आईआईटी रुड़की में एक अनुसंधान योजना के लिए वित्त पोषण के माध्यम से भी पहल की गई है; उत्तराखंड के चारधाम तीर्थ मार्ग के 100 किलोमीटर लंबाई के खंड सहित इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार (इनसार) आधारित भूस्खलन निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर अलग से हस्ताक्षर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-5 के परवानू-सोलन खंड में भूस्खलन, भूमि धंसने, जलस्तर में बदलाव का पता लगाने और सुरक्षा जाल/चट्टान अवरोधों से ढके चट्टान गिरने वाले क्षेत्र के स्थान और दैनिक स्थिति की जानकारी देने में सक्षम प्रारंभिक चेतावनी एवं अलर्ट प्रणाली स्थापित करने की भी योजना है।

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित निधि आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित नहीं है।

अनुलग्नक

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानसून का प्रभाव के संबंध में श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1879 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

हिमाचल प्रदेश में 2025 मानसून के दौरान भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विवरण, यातायात बहाली की स्थिति, अस्थायी और स्थायी बहाली कार्यों की स्थिति, स्वीकृति की स्थिति और स्थायी बहाली के लिए समय-सीमा सहित विस्तृत जानकारी।

अनुभाग	एनएच सं.	क्षति की लंबाई (मीटर में)	यातायात बहाली की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अस्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	जीर्णोद्धार कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति
एनएचएआई को सौंपे गए खंड								
किरतपुर-मनाली	205, 154, 03	15,165	(i) 3230 मीटर के क्षेत्र में यातायात पूरी चौड़ाई में बहाल कर दिया गया है। (ii) 11,935 मीटर के आंशिक/कम चौड़ाई वाले हिस्से में यातायात बहाल कर दिया गया है।	जून, 2026	544	80.42 करोड़ रुपये स्वीकृत	388 करोड़ रुपये स्वीकृत।	अस्थायी मरम्मत के माध्यम से कुल्लू-मनाली मार्ग जुड़ गया है और दो लेन में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है तथा मनाली बाईपास की संपर्कता बहाल हो गई है। 9 स्थानों की स्थायी मरम्मत के लिए बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं तथा अन्य स्थानों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

अनुभाग	एनएच सं.	क्षति की लंबाई (मीटर में)	यातायात बहाली की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अस्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	जीर्णोद्धार कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति
परवानो-सोलन-शिमला	5	680	सभी स्थानों से कीचड़ हटा दिया गया है; सर्विस रोड 50 मीटर की लंबाई में बंद है;	मार्च, 2026	26	3.5 करोड़ रुपये स्वीकृत	-	भूस्खलन से प्रभावित सभी स्थानों से मलबा हटा दिया गया है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।
शिमला-मटौर	205, 103, 03, 503	2,595	100 मीटर की लंबाई को छोड़कर पूरी चौड़ाई में यातायात बहाल कर दिया गया है।	दिसंबर 2025	7	अनुबंध के दायरे में अस्थायी बहाली	7.87 करोड़ रुपये स्वीकृत।	अस्थायी जीर्णोद्धार पूरा हो गया है। 2 स्थानों को छोड़कर स्थायी जीर्णोद्धार पूरा हो गया है।
पठानकोट-मंडी	154	2,165	600 मीटर को छोड़कर बाकी सभी रास्तों पर यातायात बहाल कर दिया गया है।	दिसंबर, 2025	32	0.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।	13.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।	अस्थायी जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गए हैं। स्थायी जीर्णोद्धार कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
उप-योग (एनएचएआई)		20,605			609	स्वीकृत राशि - 84.80 करोड़ रुपये	स्वीकृत राशि - 409.34 करोड़ रुपये।	

अनुभाग	एनएच सं.	क्षति की लंबाई (मीटर में)	यातायात बहाली की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अस्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	जीर्णोद्धार कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति
राज्य पीडब्ल्यूडी/एमओआरटीएच पीआईआई को सौंपे गए खंड								
बानीखेत - चंबा - भरमौर	154ए	13,500	यातायात	जून, 2026	235	वित्त वर्ष 24-25 में 2.41 करोड़ रुपये स्वीकृत; 19.5 करोड़ रुपये की एफडीआर आवंटित और 09.12.2025 तक अनुमानित 26.78 करोड़ रुपये स्वीकृत।	पीबीएमसी के आपातकालीन कार्यों के तहत 3.29 करोड़ रुपये स्वीकृत; विशेष मरम्मत के लिए 93.36 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट स्वीकृत।	स्वीकृत कार्यों को शुरू कर दिया गया है।
सैंज - लुहरी - ऑट	305	21,380	यातायात	जून, 2026	50		पीबीएमसी के आपातकालीन कार्यों के तहत 2.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए; 2.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।	स्वीकृत कार्य शुरू कर दिया गया है।
थियोग - हटकोटी	705	9,350	यातायात बहाल	मई, 2026	10		-	-
शिमला-रामपुर-वांगटू-कौरिक	5	38,750	यातायात बहाल	मई, 2026	30		पीबीएमसी के तहत 0.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।	स्वीकृत कार्य शुरू किया गया

अनुभाग	एनएच सं.	क्षति की लंबाई (मीटर में)	यातायात बहाली की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अस्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	जीर्णोद्धार कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति
घोंघा - हटकोटी	707	3,160	यातायात बहाल	जनवरी 2026	5		-	ईपीसी अनुबंध के तहत जीर्णोद्धार कार्य किए गए।
मैकलोडगंज - धर्मशाला	503	1,560	किमी 14/590 से किमी 16/00 तक के हिस्से को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में यातायात सामान्य है, इन हिस्सों के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। दिसंबर 2025 के अंत तक यातायात सामान्य होने की संभावना है।	मई, 2026	25		0.94 करोड़ रुपये के आपातकालीन कार्य को मंजूरी दी गई।	स्वीकृत कार्य कार्यान्वयन के अधीन है
बंखंडी - भोटा	503ए	230	यातायात बहाल	जून, 2026	-		0.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।	0.17 करोड़ रुपये के स्वीकृत कार्य शुरू किए गए।
हमीरपुर-करनोहल-कलवाहन-मंडी	3	11,080	यातायात बहाल	मई, 2026	10	-	-	ईपीसी अनुबंध के अंतर्गत किए गए कार्य
पीआईयू पांवटा साहिब	707	1,250	यातायात बहाल	जून, 2026	10	-	-	ईपीसी अनुबंध के अंतर्गत किए गए कार्य

अनुभाग	एनएच सं.	क्षति की लंबाई (मीटर में)	यातायात बहाली की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	अस्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	स्थायी जीर्णोद्धार कार्यों की स्वीकृति की स्थिति	जीर्णोद्धार कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति
उप-योग (राज्य के दिव्यांगजन + रोग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के पीआईआईयू)		1,00,260			375	स्वीकृत राशि - 29.19 करोड़ रुपये।	स्वीकृत राशि - 103.67 करोड़ रुपये।	
कुल		1,20,910			984	स्वीकृत राशि - 114 करोड़ रुपये।	स्वीकृत राशि - 513 करोड़ रुपये।	

*****